SHRI SATYA BRATA MOOKHERJEE: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

SHORT DURATION DISCUSSION
Growing unemployment in the Country

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारी से हमारे मुल्क की तकदीर और तस्वीर पर काफी असर हुआ दिखाई देता है। मैं अपनी बात हमारे मुल्क के वज़ीरे-आज़म श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात से शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने 15 अगस्त, 1998 को प्रधानमंत्री के रूप में यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों में 10 करोड़ लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे और उसके बाद इन्हीं घोषणावीर प्रधानमंत्री ने दिसंबर, 2001 को यह कहा कि भारत के नौजवान सरकारी नौकरियों की उम्मीद छोड़ दें, रोजगार के लिए वे या तो निजी क्षेत्र का दरवाजा खटखटाएं या खुद अपना उद्यम शुरू करें।

महोदय, जब इस देश के वज़ीरे-आज़म खुलेआम यह कह रहे हों कि इस देश की तरुणाई के लिए रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है तो उस देश के भविष्य के बारे में कल्पना की जा सकती है। एक तरफ यह कहा जाता है कि नौजवान इस देश का भविष्य हैं और दूसरी तरफ उन नौजवानों को रोजगार न दिलाया जाकर यह कहा जा रहा है कि नौजवान सरकार की ओर न ताकें।

महोदय, डिसइन्वैस्टमेंट की पॉलिसी के जरिए, डाऊनसाईजिंग की पॉलिसी के जरिए उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह देश के लिए दुर्भाग्यजनक है और यह बहुत ही दयनीय स्थिति है और इस देश की बागडोर ऐसा मुखिया संभाले, यह और भी दयनीय स्थिति है।

मान्यवर, बेरोजगारी के व्यापक स्वरूप की ओर जब हम ध्यान दौड़ाते हैं तो हम पाते हैं कि बेरोजगारी की वजह से देश में अशांति फैलती है, अराजकता फैलती है और जिस आतंकवाद की दुहाई समय-समय पर दी जाती है, जिसके लिए हम सब चिंतित हैं, उस आतंकवाद को भी हवा मिलती है। एक तरफ दिल्ली के लाल किले से 15 अगस्त, 1998 को एक वचन प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाए और दूसरी तरफ उस वचन के प्रति प्रतिबद्धता न निभाई जाए, उससे पल्ला झाड़ लिया जाए और इस देश में बेरोजगारी बढ़ती जाए और बढ़ती बेरोजगारी के बारे में सरकार बेखबर हो तो सरकार के क्रियाकलापों पर कई प्रकार के प्रश्नवाचक चिह्न लग जाया करते हैं।

महोदय, इस देश में ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे रोजगार के अवसर मिलें और बढ़ें लेकिन हमारे यहां बेरोजगार लोगों की फौज बढ़ती जा रही है, रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है और आज स्थिति यह है कि बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ी

चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि इन्सान की मौलिक आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। लेकिन इस रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में मैं यह कहूं कि एक शब्द और इसमें जोड़ा जाना चाहिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज भारत में आम इन्सान की मौलिक आवश्यकता यदि कोई हो गई है तो वह रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान हो गई है। इसका कारण क्या है? जब हम इनकी तरफ दृष्टिपात करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक तो हमारे देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति है जो क्लर्क उत्पन्न करती है वह इसका एक कारण है। स्वयं मैथिलीशरण गुप्त ने "भारत भारती" में लिखा, "शिक्षित तुम्हारा नाश हो, तू नौकरी के हित बनी।" ऐसी शिक्षा जो केवल क्लर्क उत्पन्न करे, ऐसी शिक्षा जो रोजगारोन्मुखी न हो, ऐसी शिक्षा जिसको अर्जित करने के बाद नौजवान स्वावलम्बी न हों बल्कि परावलम्बी हों और अपने भविष्य के प्रति सरकार पर आश्रित हों, मैं सोचता हूं कि उस शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने के बारे में हमको विचार करना चाहिए। बात आती है कि आज यह बेरोजगारी का संकट हमारे देश में क्यों उत्पन्न हो रहा है? जब हम उन आंकड़ों को देखते हैं जो बेरोजगारी की एक भयावह तस्वीर पेश करती है तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो रूरल यूथ हैं, उनका यदि अनएम्पलायमेंट रेट देखा जाए और उस एक ग्रुप को देखा जाए जो नौजवानों का ग्रुप माना जाता है 15 से 24 ऐज ग्रुप का तो उसका अनएम्पलायमेंट रेट 57 से 64 पर-एक हजार बढ़ा है। जहां तक लेबर फोर्स की संख्या को देखा जाय और दूसरी तरफ जो अनएम्पलायमेंट रेट है, उसके आंकड़ों को हम देखें तो उनमें जो वृद्धि हुई है वह 97 से 124 मेल्स के लिए हुई है और फिमेल्स के लिए 83 से 125 हुई है। जो इस बात को इंगित करती है कि हमारे यहां जो बेरोजगारी की समस्या है वह महिलाओं में बहुत ज्यादा है और यह गांवों में और भी ज्यादा है। प्रश्न यह है कि गांवों में बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोत्तरी क्यों हो रही है। इसका एक कारण यह भी है कि लोग अपने खानदानी व्यवसाय से हटते जा रहे हैं। हमारे श्रम मंत्री जी खुद गांव से ताल्लुक रखते हैं, मैं सोचता हूं कि वह इस बात की पुष्टि करेंगे कि गांवों में पहले लुहार, सुनार, मोची हुआ करते थे। अब उनके बच्चे पढ़ लिखकर बड़े होते हैं तो जो एक पारम्परिक खानदानी व्यवसाय है उसके प्रति उनकी दिलचस्पी नहीं रहती है। मैं सोचता हूं कि यह इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो गांवों में संसाधन हैं, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसोर्सेस हैं, उनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है और उसका उपयोग किस ढंग से हो, उस बात की जानकारी हम समय रहते उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। यही कारण है कि बेरोजगारों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जब हम दूसरे आंकड़ों की तरफ गौर करते हैं कि नौजवानों में और खासतौर पर ग्रामीण नौजवानों में अनएम्पलायमेंट की क्या स्थिति है और यदि हम 1993-94 में नौजवानों के बीच अनएम्पलायमेंट के प्रतिशत को देखते हैं तो खुद सरकार के आंकड़े इस बात की पुष्टि करेंगे कि यह 2.94 प्रतिशत थी जो कि 1999-2000 में बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गई है। यदि हम सारे ऐज ग्रुप पर नजर दौड़ाते हैं तो वह बेरोजगारों का प्रतिशत 5.6 प्रतिशत था जो कि बढ़कर 1999-2000 में 7.2 प्रतिशत हो जाता है। संख्या में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन समय समय पर स्वयं जो सरकारी उत्तर मिला है, वह इस बात का सबूत पेश करेगा कि बेरोजगारों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। 1999-2000 में जहां उनकी संख्या 9.05 मिलियन थी, ऐसी उम्मीद की जाती है कि यह संख्या बढ़कर 2007 में 25.94 मिलियन हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो मांटेक सिंह अहलुवालिया कमेटी का गठन किया गया था, उसके खुद के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे यहां जो रोजगार चाहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। जहां 1999-2000 में उनकी संख्या 406.05

मिलियन थी, वह बढ़कर 2007 में 462.12 मिलियन हो जाएगी और इसके लिए 1.8 प्रतिशत एनुअल ग्रोथ की आवश्यकता होगी। यह सारी स्थितियां निश्चित रूप से हमारे सामने कान खड़े करने वाली स्थितियां हैं। मान्यवर, दूसरा और पहलू है कि जब इनवैस्टमेंट बराबर नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से जिन रोजगारों को सृजित करने की बात कहते हैं, वह भी नहीं हो पाएगी। 1985-86 में स्थिति यह थी कि जो कैपीटल साइड्स में सेविंग थी, वह 573 करोड़ रुपये थी और 2001 में, अगर हम बजट की तरफ देखें तो 2001-2002 में जो कैपीटल साइड के अनुमानित रुपये थे, वह घटकर मात्र 79 हजार करोड़ रुपये हो गये थे। यह इस बात का सबूत देते हैं कि हमारा बजट के प्रति, इनवैस्टमेंट के प्रति नजरिया क्या है? यह निश्चित रूप से चौंकाने वाली स्थिति पैदा करते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और भी कुछ आंकड़े हैं जिनकी तरफ यदि हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमारे सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम जहां एक तरफ फंड यूटीलाइजेशन की बात करते हैं - खुद सरकार का इस सदन में उत्तर है - उसके हिसाब से 1999-2000 के लिए जो पैसा रोजगार सृजन के लिए दिया गया था, उसका जो टोटल फंड अवेलेबल है, उसका यूटीलाइजेशन अगर हम देखते हैं तो मात्र 74 प्रतिशत हुआ है। यह खुद सरकारी जवाब है जिसकी कॉपी मेरे सामने है। जब अलग अलग स्कीम्स में हम रोजगार सृजित नहीं करेंगे तो हम कैसे बात कर पाएंगे कि हम बेरोजगारी की समस्या के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित हैं। अब हम जब अपनी नजरें दौड़ाते हैं, जवाहर रोजगार योजना के ऊपर, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के ऊपर और इंदिरा आवास योजना के ऊपर तो इसमें भी जो टारगेट रखे गये हैं, वह फिक्स नहीं किये गये हैं। यह भी सरकार के उत्तर में स्पष्ट है। महोदय, हम एक तरफ तो इन योजनाओं को बना देते हैं लेकिन जब हम उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं करते तो जिन योजनाओं को हम बनाते हैं, उनके संबंध में हमारी जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वह सही मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है और यही स्थिति है कि जब हम रोजगार सृजित नहीं कर पा रहे हैं तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। खुद सरकारी आंकड़े फिर से इस बात की पुष्टि करेंगे कि जो अनुमानित बेरोजगारों की संख्या है वह जहां 2000 में 9.05 मिलियन कही गयी है वह 2007 में बढ़कर 25.94 मिलियन हो जाएगी और बाद में उसकी संख्या 2012 में 37.42 मिलियन हो जाएगी। यह स्थिति बन गयी है। इस संबंध में निश्चित रूप से हमें विचार करना पड़ेगा कि कहां कमी है। जब हम 1981 से 1991 के बीच में ग्रोथ रेट के ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो पब्लिक सैक्टर में इम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट पर-ऐनम 2.1 प्रतिशत आता है। जो घटकर 1991-1998 के बीच में 0.2 प्रतिशत हो जाती है। अब बात आती है कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट के एम्पलाइमेंट ग्रोथ रेट क्या हैं? 1981-91 के बीच में हम नजर दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि वह 0.7 प्रतिशत है, जो घटकर 0.6 प्रतिशत हो जाते है। ये सारी बातें इस बात की पुष्टि करेंगी कि कहीं न कहीं हमारे योजनाकारों के योजना बनाने में कुछ कमियां हैं और वे कमियां ये हैं कि वे लोगों को रोजगार देने के बारे में बहुत ज्यादा कनसर्न नहीं हैं। मैं कह रहा था कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी का स्वरूप क्या है और बेरोजगारी का संकट क्यों बढ़ता जा रहा है? बेरोजगारी भी तीन प्रकार की है, एक बेरोजगारी वह है जो ऐसे बेकार पैदा कर रही है, जो पढ़े-लिखे बेकार हैं। एक बेरोजगारी वह है जो ऐसे बेकार पैदा कर रही है जो अर्ध-शिक्षित बेकार हैं और एक वे लोग हैं जो साधनहीन बेकार हैं। इस प्रकार बेकारों की समस्या के बारे में सरकार को विचार करना पड़ेगा, एक वे जो शिक्षित हैं, एक वे जो अर्ध-शिक्षित हैं और एक वे जो साधनहीन बेकार हैं। जब हम इन पर विचार करेंगे, उनके बारे में कुछ योजनाएं तैयार करेंगे तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं तब इस बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी।

मान्यवर, मैं आपके जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब हम कारणों पर जाते हैं तो जहां शिक्षा एक कारण है, वहीं बढ़ती हुई आबादी भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो प्रपोर्सन आबादी का है अगर हम उस पर अंकुश नहीं लगा पाए, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो हम बेरोजगारी पर नियंत्रण नहीं कर सकते। यह एक दूसरे के अनुपात में है। इसके बारे में भी सरकार को नीति निर्धारित करनी पड़ेगी वरना इस देश की जो तरुणाई है, आए दिन बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंसती रहेगी और हम उस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम राजनीति से ऊपर उठकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं और सरकार भी एक दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ बेरोजगारी से निपटने के लिए न केवल योजनाएं बनाएं बल्कि उन योजनाओं को क्रियान्वित करें और उन मूल कारणों में जाए जिनकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मान्यवर, बात आती है कि सरकार ने जो डाउन साइजिंग का निर्णय लिया है, कुछ पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स के मामले में डिस-इन्वेस्टमेंट का निर्णय लिया है, इससे क्या स्थिति होगी। जब सरकारी उद्यमों में लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे, जब हम खुद वालेंट्री रिटायरमेंट स्कीम बनाएंगे और उसके तहत लोगों को रिटायर करते जाएंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा तो निश्चितरूप से सरकार को विचार करना पड़ेगा कि आखिर कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हमारी योजनाओं में कमी है और यही कारण है कि जहां एक तरफ वीआरएस से उस संख्या में कमी आ रही है ...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU) : You have very rightly raised a point about downsizing. I would like to be enlightened in this regard. What is your thinking about it? Downsizing is being done by the State Governments also. Are you suggesting an alternative or are you simply saying that डाउन साइजिंग नहीं होनी चाहिए?

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, मात्र मैं इस डिसकसन में पार्टिसिपेट करूं इस नजरिए से, मैं इस समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा हूं और इसलिए मैं केवल सरकार की गलतियों को ही इंगित नहीं कर रहा हूं, कारणों पर जा रहा हूं और कारणों के बाद निदान पर भी जाऊंगा। प्रश्न इस बात का है कि हमारे माननीय मंत्री जी थोड़ा संयम बरतें और कुछ धैर्य रखें तो निश्चितरूप से उन्हें उस निदान को भी सुनने का अवसर मिलेगा। मान्यवर, जहां मैंने एक तरफ दूषित शिक्षा प्रणाली का जिक्र किया है वहीं बढ़ती हुई जनसंख्या का भी जिक्र किया है। दूसरी तरफ जो एम्पलाइमेंट एक्सचेंज में भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है, चाहे वह किसी भी राज्य में हो, हमें एम्पलाइमेंट एक्सचेंज के भ्रष्टाचार को कम करने के बारे में विचार करना पड़ेगा। समय रहते लोगों को जो जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है, उस जानकारी के बारे में भी हमको देखना पड़ेगा। वह जानकारी लोगों को सही मिल पाए। उस व्यावसायिक व रोजगारोन्मुख शिक्षा की तरफ हम ध्यान दें जिससे लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति मिल सके।

अब बात आती है कि मल्टी नेशनल कंपनीज का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हम समय रहते ड्यूटी नहीं बढ़ाते जिससे हमारे देश में इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। एग्रीकल्चर की फील्ड में यह बात खास तौर पर लागू होती है कि समय रहते जहां यह सरकार कई नीतिगत मामलों पर ऐक्ट नहीं करती है, रिएक्ट नहीं करती है वहीं जो ड्यूटी बढ़ानी चाहिए वह भी नहीं बढ़ा पाती है और जब इस देश के किसान की बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है, जिस किसान के बारे में यह कहा जाता है कि 75 प्रतिशत से अधिक वे लोग हैं जो किसान व्यवसाय से संबंधित हैं, तब भारत की दयनीय स्थिति पर भी विचार किया जा सकता है और इसका लाभ मल्टी नेशनल कंपनीज को ही मिला करता है। इस बढ़ते शिकंजे पर भी हमें विचार करना चाहिए, इस बारे में गौर करना चाहिए।

शिक्षा की बात आती है कि शिक्षा किस प्रकार की दी जाए? हमारे यहां एग्रीकल्चर में, बायो-टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात आती है, एडवांस टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात आती है लेकिन जो तकनीकी शिक्षा हमारे देश के नौजवानों को दी जाती है उस तकनीकी शिक्षा में भी कुछ न कुछ विसंगतियां होती हैं। जो महंगी तकनीकी शिक्षा दी जाती है उसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए।

एक बात यह है कि लोगों का मन श्रमजीवी बनाना चाहिए। कई लोगों की मानसिक स्थिति यह है कि वे बेकार रहना पसंद करते हैं, खाली बैठना पसंद करते हैं लेकिन मेहनत करना पसंद नहीं करते। हमें उनकी यह मानसिकता खत्म करनी पड़ेगी। हम केवल भाग्य निर्माताओं पर ही निर्भर न रहें बल्कि हमें खुद भी कुछ करना चाहिए जैसाकि कहा भी गया है कि गोड हैल्प दोज हू हैल्प देमसैल्वज। जब हम खुद अपने आपको काबिल करेंगे, अपने आपको तैयार करेंगे तो हम भाग्य निर्माताओं के भरोसे नहीं बैठेंगे। जब इस देश की बागडोर घोषणावीर लोगों के हाथों में होगी तो उनके भरोसे बैठना तो बिल्कुल ही बेकार होगा।

प्रश्न उठता है कि क्यों शहरी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? क्यों पलायन गांवों से शहर की तरफ होता जा रहा है? हमें उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। क्यों लोग नशीली दवाइयों का सेवन कर रहे हैं? क्यों आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं? क्यों काम के लिए तरसते हाथ सरकार की तरफ निहार रहे हैं और सरकार कुछ कदम नहीं उठा पा रही है? यह कहा जाता है कि हमारी वित्तीय स्थिति बहुत सीमित है और सीमित साधनों और संसाधनों की वजह से हम उतने लोगों को रोजगार प्रदान नहीं कर सकते जितने लोगों को प्रदान करना चाहिए। जब यह विवशता सरकार दिखाती है तब निश्चित रूप से हमें एक ऐसी स्थिति निर्मित करनी होगी जिससे हम आत्मनिर्भर बनें और खुद के काम प्रारंभ कर सकें। मान्यवर, बात आती है कि जो सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाते थे वे पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जो गवर्नमेंट के पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज हैं उनमें कराए जाते थे लेकिन आज स्थिति यह है कि उनमें डाउन साइजिंग की एक प्राब्लम चल रही है। यह कहा जाता है कि वेतन आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए इतना ज्यादा वेतन बढ़ा दिया गया है कि अब जो अलग-अलग स्टेट्स हैं उनकी वित्तीय स्थिति ऐसी हो गई है कि उसमें कमियां लाई जा रही हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए आपका क्या सुझाव है? वित्त मंत्रालय ने एक सर्कुलर हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भेजा कि आप डाउन साइजिंग करिए। वह सर्कुलर वहां की पहल

3.00 p.m.

पर नहीं है वह यहां की पहल पर गया है कि आप अपनी-अपनी स्टेट में यह निर्णय लीजिए कि डाउन साइजिंग हो क्योंकि वित्तीय स्थिति वैसी नहीं है। प्रश्न यह है कि डाउन साइजिंग कहां की जाए, किन के लिए की जाए? क्या क्लास थ्री या फोर के लिए की जाए या क्लास वन के लिए की जाए? वी.आर.एस. स्कीम प्रारंभ की गई, वी.एस.एस.स्कीम प्रारंभ की गई। अगर उन आंकड़ों को आप देखें कि वी.आर.एस. से ज्यादा लाभान्वित कौन-सी क्लास के लोग हैं? मान्यवर, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है और मैं वह आकड़े माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दूंगा कि खुद वीआरएस की स्कीम में अगर कोई वर्ग लाभान्वित रहा है तो वह अफसर वर्ग रहा है, क्लास वन और क्लास टू आफिसर वर्ग रहा है और क्लास थ्री और क्लास फोर वर्ग इससे लाभान्वित नहीं हुआ। वह वर्ग इससे लाभान्वित नहीं हुआ है जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास और शोषित वर्ग से आता है। यदि आप इन आकड़ों को देखें तो आपको पता लगेगा कि डिसइन्वेस्टमेंट आप जिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का कर रहे हैं, उनमें रोजगार की सुनिश्चितता आपने तय नहीं की है कि जिन लोगों को इस डिसइन्वेस्टमेंट के तहत निकाल दिया जाएगा उनको वापस रोजगार में रख दिया जाएगा। यह कहा जाता है कि हम ऐसे डाइरेक्शन दे देंगे कि जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के क्लास थ्री और क्लास फोर इम्पलाईज हैं, वे बेरोजगार न हों। एक होता है डाइरेक्शन देना और एक होता है कानून बनाना। आदमी की नीयत और नियती दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। देश में बेरोजगारी की जो समस्या है वह विकराल और भयावह रूप धारण करती जा रही है। अगर समय रहते इस पर अंकुश न लगा पाए तो इस देश के भविष्य पर ग्रहण लग जाएगा और यह देश प्रगति और विकास के द्वार पर दस्तक नहीं दे पाएगा, यह मेरी स्पष्ट मान्यता है।

मान्यवर, दूसरी बात यह हो रही है कि जो सरकारी उद्यम हैं, उनका कौड़ियों के दाम में डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है और खासतौर से उन लोगों के हाथों में दिया जा रहा है जो सरकार के कृपा पात्र लोग हैं, जिनको उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को चलाने का कोई अनुभव नहीं है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा लेकिन क्योंकि मंत्री जी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की है इसलिए मैं उसका उत्तर संकेत में दे रहा हूं। ऐसे हालात में लोगों को सही रोजगार नहीं मिल पाएगा, रोजगार सही सृजित नहीं हो पाएंगे। इसलिए आवश्यकता यह है कि शासन अपनी फर्ज-अदायगी करे, प्रशासन भी अपनी फर्ज अदायगी करे और जो प्रतिनिधि हैं, वे भी अपनी फर्ज अदायगी करें। अपने कर्तव्य से जब वह विमुख होंगे, अपने उत्तरदायित्व का जब वह सही निर्वहन नहीं कर पायेंगे तो देश में बेरोजगारों की जो स्थिति है, वह दिन प्रति दिन भीषण होती जाएगी।

दूसरी बात यह है कि एक भेड़-चाल चल पड़ी है कि ऐसी कौन सी स्कीम बनायें जिससे पूंजिपति लाभान्वित हों, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले ऐसी कोई स्कीम न बनायें। तो इसके बारे में भी इस सरकार को विचार करना पड़ेगा। इस सरकार को अगर इसके निदान की बात करनी है तो उसे यह विचार करना पड़ेगा कि ग्रामीण उद्योग धंधों को कैसे बढ़ावा मिले। इस सरकार को इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की अधिक

संभावनायें बढ़ें और गांवों के जो सीमित साधन हैं उनका सही उपयोग हो और अज्ञानता की वजह से जो इस देश के ग्रामीण नौजवान की स्थिति चौपट होती जा रही उस स्थिति से कैसे उबर कर ऊपर आएं।

महोदय, मैं दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपकी आंखें मेरे पर लगी हुई हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mr. Pachouri, thirty-six minutes have been allotted to your Party. You have already consumed 26 minutes. Perhaps, your other colleagues, who have to speak after you, may not be able to speak then. That is my anxiety.

SHRI SURESH A. KESWANI (Maharashtra) : He has not yet touched even the tip of the iceberg.

श्री सुरेश पचौरी : यह बड़ा इम्पार्टेंट सबजेक्ट है। यह देश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है और मैं सोचता हूं कि जहां हम इससे चिंतित हैं आप भी इस समस्या से चिंतित होंगे। मैं अब कुछ सुझाव देना चाहूंगा। कमियां और खामियां ही मैंने अभी तक बताई हैं। इस सरकार की कमियां और खामियां वाकई इतनी हैं कि जितना भी उनका वर्णन किया जाए, वह कम है। लेकिन मैं सोचता हूं कि इस सरकार को कुछ सुझाव दूं हो सकता है कि समय रहते वह कुछ कदम उठाये और इस देश की तरुणाई का उद्धार हो जाए।

मान्यवर, जो भी योजना तैयार हो, जो भी राष्ट्रीय योजना सरकार की तरफ से तैयार हो, उसकी पहली शर्त यह होनी चाहिए कि वह रोजगार का सृजन करे और बेरोजगारी पर नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाए और उस पर अमल करने के लिए एक सहमति की स्थिति निर्मित की जाए। जो वित्तीय संसाधन हैं, जिनसे रोजगार सृजित होते हों उनको पारदर्शी बनाना चाहिए और छोटे छोटे उद्योग प्रारंभ करने के लिए बैंक की जो शर्तें हैं उनको शिथिल करने की आवश्यकता है। साथ ही जो छोटे छोटे रोजगार प्रारम्भ किए जाते हैं उनकी जानकारी समय रहते नौजवानों को उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो कृषि से संबंधित उद्योग हैं, जो गांवों में जरूरत के हिसाब से संसाधन हैं, उनको भी बढ़ावा देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुटीर उद्योगों को भी उचित प्रोत्साहन और संरक्षण देने की जरूरत है। साथ ही यह भी जरूरत है कि जो इंपलायमेंट एक्सचेंज में अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार है, उन पर कैसे अंकुश लग सके और एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण हम लोग अपनाएं जिससे लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोज़गार उपलब्ध हो सके क्योंकि जो हम नीतियां और घोषणाएं करते हैं ऐसा नहीं लगना चाहिये कि यह केवल भाषण में करने के लिए घोषणाएं हैं, नीतियां कागज़ पर नहीं हैं बल्कि उन नीतियों का जो सफर है, जो यात्रा है, वह असलियत में दिखाई देनी चाहिये तब हम बेरोजगारी का सामना कर पाएंगे और हम एक उन्नत स्वाभिमानी भारत के जो नौजवान हैं उनको निराश और हताश होने से बचा पाएंगे। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही आग्रह है।

अब प्रश्न उठता है कि बेरोजगारी निदान के लिए और कौन कौन सी, किस प्रकार की योजनाएं बनाएं। मैं सोचता हूं कि इस मामले में खुद सरकार यह बताए कि जिन योजनाओं को बेरोजगारी दूर करने के लिए बनाया गया था, वे योजनाएं अपने लक्ष्य की पूर्ति क्यों नहीं कर पाई हैं और उन योजनाओं के लिए जितना पैसा रखा गया था, उस पैसे का पूरा यूटीलाइज़ेशन क्यों नहीं हो पाया है। समय ज्यादा हो गया है, इसलिए कितना पैसा किस योजना में रखा गया था और उस पूरे पैसे का यूटीलाइज़ेशन नहीं हो पाया, मैं सोचता हूं कि मंत्री जी जब जवाब दें तो उन आंकड़ों को उठाएं कि कितना पैसा जवाहर रोजगार योजना के तहत था जिसका केवल 74 प्रतिशत यूटीलाइज़ेशन हुआ है। इस कम यूटीलाइज़ेशन के क्या कारण हैं और कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो बेरोजगारी की समस्या है इसका सीधा संबंध इस देश की जनसंख्या से जुड़ा हुआ है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और राष्ट्रीय चुनौती है। इसलिए इसे दूर दृष्टि के आधार पर पक्के इरादे को दृष्टिगत रखते हुए, दृढ़ इच्छाशक्ति रखते हुए सब को मिल जुल कर इस समस्या से उबारने के लिए कोशिश करनी चाहिये और सरकार को बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त इस देश की तरुणाई को मुक्ति दिलाने के लिए वरीयता के आधार पर आगे आना चाहिये। ऐसा मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोडकर) : धन्यवाद पचौरी जी। You have referred to an English idiom "God helps those who help themselves". In Hindi, there is a beautiful couplet "खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है।"

श्री कैलाश जोशी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी के प्रश्न पर पिछले वर्ष इस सदन में एक गैर सरकारी विधेयक भी प्रस्तुत हुआ था और उस विधेयक में जो कुछ बोला गया था, लगभग उससे मिलती-जुलती बात आज भी सदन में कही गई है।

श्री सुरेश पचौरी : वह विधेयक भी हमारा ही था।

श्री कैलाश जोशी : वही याद दिला रहा हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान परिस्थिति में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों को ध्यान में रख कर हम रोजगार के अधिकतम अवसर कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, इस पर सदन को विचार करना होगा। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष प्राचीन काल से एक अत्यंत समृद्ध देश रहा है। यहां पर सब प्रकार की कला, कौशल था, सब प्रकार की वस्तुएं बनती थीं। यहां की कृषि भी बड़ी समृद्ध थी। हम केवल अपने लिये ही यह सब उत्पन्न नहीं करते थे बल्कि दुनिया के देशों में हमारे यहां की सामग्री जाया करती थी। यहां का कपड़ा, यहां के आभूषण, यहां के मसाले, यूरोप तक के लोग उसके लिए तरसते रहते थे। परन्तु समय ने करवट ली, परिवर्तन हुआ, विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमले किये, हमारी सारी समृद्धि को एक एक करके लूट कर ले गये। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था उसको भिखारी बनाने में कोई कसर विदेशी हमलावरों ने नहीं रखी। उस परिस्थिति में से गुजर करके भी हमारे देश के समाज ने अपने आपको जीवंत बनाए रखने के लिए जो प्रयास किए जा सकते थे वे सारे प्रयास उन्होंने किए। अंग्रेजों के आने तक यह

क्रम चलता रहा। अंग्रेजों ने इस देश का जितना शोषण किया, शायद किसी और विदेश के हमलावर ने नहीं किया होगा। परंतु वह बात जब पुरानी होने लगी और स्वाधीनता संग्राम आरंभ हुआ तो स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी का ध्यान सबसे पहले इन सब बातों की ओर गया। उन्होंने केवल राजनीतिक स्वाधीनता की बात नहीं की। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में कुछ अन्य विषयों को जो इस देश के भविष्य से जुड़े हुए थे, पूरी तत्परता से उठाया था। मैं विस्तार से तो उनमें नहीं जाना चाहता हूं किंतु एक ही बात याद दिलाना चाहता हूं सदन के माननीय सदस्यों को कि महात्मा गांधी ने कहा था कि तब तक हमारी आजादी अधूरी रहेगी जब तक हम गांवों को फिर से आत्मनिर्भर नहीं बना देते, तब तक हमारी आजादी अधूरी रहेगी जब तक गोवंश की हत्या पर रोक नहीं लगती, तब तक हमारी आजादी अधूरी रहेगी जब तक हमारे देश की भाषा में जिसको सर्वसामान्य व्यक्ति समझ सके, उसमें हमारे देश का राजकाज नहीं चलेगा। ये तीनों बातें मुख्य रूप से कही गयीं।

अभी माननीय सदस्य का भाषण मैं सुन रहा था। वे सदन की दृष्टि से मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं। उनको इसका बड़ा लम्बा अनुभव है। अभी उनकी बातों को मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हमको कुटीर उद्योगों को बढ़ाना चाहिए, हमें ग्रामीण उद्योगों को बढ़ाना चाहिए। क्या 1998 के बाद इनको बढ़ाने की आवश्यकता हुई? इन कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को किसने तहस नहस किया? ये कब से तहस नहस होने लगे? मैं उनके कारणों में आज नहीं जाना चाहता हूं लेकिन निश्चित रूप से उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि गांव के सारे उद्योग इन 50 वर्षों में हमारी गलत नीतियों के कारण चौपट हुए हैं। लकड़ी जंगल में होती है लेकिन लकड़ी का सामान शहरों में बनेगा। कपड़ा पहले गांवों में बना करता था। हम बचपन में देखा करते थे कि हमारे यहां पर गांव-गांव में बुनकर हुआ करते थे। कपड़ा बुनते थे। कपड़ा बुनकर लोगों को पहनने को दिया करते थे। लेकिन आज वे सारे बुनकर समाप्त हो गए। गांव में अब न तेल बनता है न लोहार रहे हैं। अभी माननीय सदस्य ने याद भी दिलाया था। पहले लोहार रहते थे। आज कोई नहीं है। सब चौपट हो गए। क्या यह अभी 1998 के बाद ही हुआ है? यदि प्रारंभ से हुआ है तो आज हमें यह सोचना पड़ेगा कि फिर से इस दशा को बदलने के लिए हमें कौन से कदम उठाने पड़ेंगे। केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा कि कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, ग्रामीण उद्योग समाप्त हो गए। यह विरासत में हमको मिला है। आज वर्तमान पीढ़ी में रह कर हम इसको ठीक दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं, इसकी आज आवश्यकता है और उसमें हम सबको ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : आपने कहा था कि आप सुधार करेंगे। सुधार जब आप भी नहीं कर पा रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं तो आप इस सत्ता में रहने के हकदार नहीं हैं। यहां की बुराई बताकर कि यह गलत है, आप सत्ता में आए। आप लोगों से वादा करके सत्ता में आए। उस वायदे की पूर्ति की दिशा में कदम नहीं उठा पा रहे हैं। केवल उस समय यह हुआ तो हम यह कर रहे हैं, मतलब यह कंपटीशन हो रहा है ...**(व्यवधान)**...

श्री कैलाश जोशी : अब हम सत्ता में तो आए हैं लेकिन आए हुए अभी तीन साल ही हुए हैं ...(**व्यवधान**)... दो साल हुए हैं अभी। लेकिन आप लोगों ने 50 साल में जो मटियामेट किया उसको सुधारने में कम से कम 10 साल तो लगेंगे।

श्री सुरेश पचौरी : ये 10 साल तक देश को उसी स्थिति में खड़ा कर रखेंगे।

श्री कैलाश जोशी : इसीलिए प्रधान मंत्री ने 10 वर्ष का समय मांगा है। जहां तक आप यह कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने क्या किया तो जो कुछ इस सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में किया है मैं उसका वर्णन आपके सामने करूंगा। अभी तो आपने जो प्रश्न उठाए हैं मैं उनके संबंध में बोल रहा हूं।

श्री सुरेश पचौरी : बेरोजगारी के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उन पर प्रकाश डालिए।

श्री कैलाश जोशी : तो उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा था कि उसके बाद में दिशा उल्टी हो गयी। गांवों को बरबाद किया गया। गांव का कला-कौशल, गांव की कारीगरी, गांव का सारा काम धीरे धीरे शहरों में आकर सिमटने लगा। उसके परिणामस्वरूप गांव की दशा बिगड़ी जहां पर हमारे देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या रहा करती थी। अभी भी 70 प्रतिशत लोग गांवों के अंदर निवास करते हैं। बीच-बीच में प्रयास भी हुए। अब माननीय सदस्य को मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि हमारे यहां हथकरघा का बहुत अच्छा उद्योग था और उसका बहुत अच्छा कपड़ा बनता था। मैं मिल का कपड़ा नहीं पहनता, मैं अभी भी हथकरघा का ही कपड़ा पहनता हूं, लेकिन अब मैं देखता हूं कि उसमें भी कठिनाइयां पैदा होने लगीं हैं। आज से 15-16 साल पहले सरकार ने इस पर विचार किया कि हथकरघा के कपड़े को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने निर्णय लिया कि यह कपड़ा केवल हथकरघा में ही बनना चाहिए। मिलों में इसके बनने पर रोक लगा दी जाए। आज 15-16 साल हो गए लेकिन वह रोक नहीं लगी। उसके कारण भी हथकरघा उद्योग धीरे-धीरे सिमटता जा रहा है। यह सरकार तो फिर से प्रयत्न कर रही है कि उस हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए। उसके लिए धनराशि उपलब्ध कराने के लिए भी पिछले दो वर्षों के बजट में प्रावधान किए गए। परन्तु जो कदम हमें समय पर उठाने थे वे कदम हमने कभी नहीं उठाए और जिस दिशा में यह उद्योग जा रहा था उसको जाने दिया। केवल भाषण होते रहे, लेकिन उनको कार्यान्वित करने का प्रयास नहीं किया गया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, विदेशों में ग्रामीण उद्योगों को आज भी बढ़ावा दिया जाता है। मुझे जापान के बारे में मालूम है। जापान में जो इलैक्ट्रिक बल्ब बनते हैं और इलैक्ट्रॉनिक का जो सामान बनता है, उनके छोटे-छोटे पुर्जों को गांवों में भेज कर वहां जुड़वाया जाता है। हम भी यह कर सकते थे लेकिन जब सारी दिशा ही बदल गई तो यह नहीं हो सका। अब आज अगर उसको एक झटके में बदलने का प्रयास यह सरकार करे तो मुझे यह संभव दिखाई नहीं देता। उसके सामने कई कठिनाइयां हैं। परन्तु यह होना चाहिए और यह तभी होगा जब हम बेरोज़गारी पर अंकुश लगा सकेंगे। यूरोप के अनेक देश हैं जो केवल एक वस्तु पर समृद्ध होते चले गए। पिछले 50 वर्षों में कहीं केवल अगर अंगूर की खेती होती है तो वे उसमें ही समृद्ध हो गए, कहीं केवल

अगर दूध का काम होता है तो वे उसी में समृद्ध हो गए। केवल डेयरी पर ही उनका काम चल रहा है। प्रकृति की हम पर इतनी कृपा है कि बहुत उर्वरा भूमि हमको मिली हुई है। यहां पर बारह मासी बहने वाली नदियां हैं, बहुत समृद्ध वन हमारे देश में हैं। उस भूमि को अगर खोदा जाए तो उसके अंदर सब प्रकार के खनिज पदार्थ भरे हुए हैं। हीरा यहां मिल रहा है, पन्ना यहां मिल रहा है, सोना यहां मिल रहा है, फिर क्या कारण है कि 50 वर्षों में दिशा में परिवर्तन नहीं हुए? पचास वर्षों में अगर नहीं हुआ है तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिल कर इस बात पर विचार करें कि आखिर कौन सी कमियां थीं जिसके कारण पचास वर्षों में हम जहां पहुंच सकते थे वहां नहीं पहुंच पाए और अब दस वर्षों में पहुंचने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए, इसकी आज आवश्यकता प्रतीत होती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आगे कहना चाहता हूं कि वास्तव में हमारी प्राथमिकता तो यह होनी चाहिए थी और जो कि आज भी होनी चाहिए कि सब से पहले कृषि, उसके बाद ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और उसके बाद बड़े उद्योगों को प्राथमिकता देने की होनी चाहिए। अब यह देखने में तो बड़ा आदर्श लगता है किंतु यदि इस पर हम प्रारंभ से ही ध्यान देते तो आज हमें बेरोज़गारी की समस्या पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब आज आप सुझाव दे रहे हैं कि कुटीर उद्योग बढ़ाइये, ग्रामोद्योग बढ़ाइये, गांधी जी की जो विचारधारा थी क्या उसको ज्यों का त्यों हमारे देश में लागू किया जा सकता है? इस बीच में जो परिवर्तन आए हैं वे इतने बाधक बन गए हैं कि हम उस दिशा में अब नहीं जा सकते। इसलिए आज की परिस्थिति में हम अधिक से अधिक रोज़गार के अवसर दिलाने के लिए किस प्रकार कदम उठा सकते हैं। इस पर हमको वास्तव में विचार करना पड़ेगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी शिक्षा के बारे में भी बात हुई। अभी माननीय सदस्य ने भी कहा कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। अभी इस सरकार को बने दो साल हुए हैं इसको जब वह परिवर्तन कर रही है तो उसमें भी मीन-मेख निकाली जा रही है। उसमें भी कहा जा रहा है कि भगवाकरण हो रहा है, सांप्रदायीकरण हो रहा है, तालिबानीकरण हो रहा है। जरा उसका प्रारूप तो सामने आने दीजिए। ...(व्यवधान)... देखिए, बिना सदन की सहमति के तो कोई नीति पारित होने वाली नहीं है। अब उस पर विचार हो रहा है और इसके जो विशेषज्ञ हैं उनके अपने-अपने, अलग-अलग विचार हैं। वे कुछ भी बोल रहे हैं तो अभी से तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया तो नहीं होनी चाहिए। जब वह प्रारूप बन करके तैयार हो जाए और सदन में प्रस्तुत हो तब उसको हम पहले पढ़ लें, देख लें, फिर हम बात करेंगे तो बात बनेगी। लेकिन आज इतना धैर्य नहीं है। सुना नहीं कि बोलना शुरू हो जाते हैं। मैं भी चाहता हूं कि शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए। मैं भी सरकार से मांग करता हूं कि रोजगार मूलक शिक्षा की बात कीजिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, 1986 में जो नई शिक्षा नीति बनायी गयी थी, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया था, लेकिन 1986 से 2001 तक कोई कदम नहीं उठाया गया। तो अब हमें यह कदम उठाना होगा और जब यह कदम उठेगा तभी परिवर्तन आएगा क्योंकि मूल बात यही है कि हमारी शिक्षा नीति जितनी रोजगार मूलक होगी उतने ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उतनी ही बेरोजगारी समाप्त होगी। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से सरकार से इसकी मांग करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर हम पिछले 50 सालों के इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि देश में आज भी हजारों गांव ऐसे हैं जो कि बारह मास चलने वाले रास्तों से नहीं जुड़े हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य की बात तो छोड़ दीजिए, आज भी देश में हजारों गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। दस-दस गांवों के बीच में भी स्वास्थ्य का प्रबंध नहीं है। हर गांव में पाठशालाएं नहीं हैं। यह पिछले 50 सालों में हुआ है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि क्या हुआ है और यह सोचें कि एकदम हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा। उपसभाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है कि 7 वर्षों में देश के प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि 10 वर्षों में बेरोजगारी पर अंकुश लगा दिया जाएगा। अब आप कहते हैं कि 10 वर्ष की बात क्यों की और अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ। उपसभाध्यक्ष महोदय, औद्योगीकरण के लिए और देश में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनेक संसाधनों की आवश्यकता है। महोदय, देश में बिजली का संकट क्यों है? आज भी गांवों में कई जगह बिजली नहीं मिल पा रही है जिस से कि वहां ग्रामीण उद्योग लगाए जा सकें जब कि देश के बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े कारखानों में 10-10 घंटे बिजली मिल रही है। सभी प्रदेशों में बिजली की यही स्थिति है। तो इसे ठीक करने में कुछ समय तो लगेगा। महोदय, एक विद्युत गृह बनने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। इसलिए अगर हम यह अपेक्षा करें कि एक-दो साल में सारे संसाधन उपलब्ध हो जाएं, सारी कमियां समाप्त हो जाएं तो यह संभव नहीं है। इसे ध्यान में रखकर प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है कि 10 वर्षों में देश से बेरोजगारी का उन्मूलन कर दिया जाएगा। फिर उदारीकरण की बात आ गयी और अभी माननीय सदस्य स्वयं कह रहे थे कि वर्ष 1991 में स्थिति यह थी और 1998 में यह हो गयी। महोदय, 1991 वह वर्ष था जब कि हम ने उदारीकरण को स्वीकार किया, 1995 वह वर्ष था जब हम ने क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस को स्वीकार किया और 2001 में पूरी 1429 वस्तुओं से रिस्ट्रिक्शंस हट गया। अब यह जो कठिनाई पैदा हुई है, उस के लिए रास्ता निकालने के संबंध में कुछ सुझाव माननीय सदस्य देते तो हम समझते कि हां, उन्होंने यह सुझाव दिया कि इस कठिनाई में से इस तरह का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन उदारीकरण के कारण जो समस्याएं पैदा हुई हैं, उन का निदान तो हम को मिल-बैठकर ढूंढना होगा, तभी निदान निकलेगा। केवल आलोचना करने से काम चलने वाला नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, उस के बाद विश्व व्यापार संगठन बन गया और उस कारण भी हमारे सामने अनेक समस्याएं पैदा हुईं। कुछ प्रतिकूल समस्याएं हमारे सामने पैदा हो गयीं। अब उन के लिए भी हमें रास्ता निकालना होगा और वह तब निकलेगा जब हम प्रयत्न करेंगे। अभी यहां पर कहा गया कि मल्टी-नेशनल कंपनीज आ रही हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. के फैसले के कारण वे तो आएंगी। उन को रोकने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, वह सरकार ने समय-समय पर उठाए हैं और अभी भी लगातार सरकार उस दिशा में कदम उठा रही है। हमारे यहां पर उस का जो प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव को कम-से-कम करने या उसे समाप्त करने के लिए विचार किया गया है। बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के मामले में भी विचार किया गया है। अब बहु-राष्ट्रीय कंपनियां तो विश्व व्यापार संगठन बनने के कारण आ रही हैं, पर पेप्सी कब आया? मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि वह मुझे बताएं कि जब पेप्सी वाले पंजाब में आए थे तो उन्होंने कितने लोगों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था? उपसभाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार को लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन उन में से 1/6 लोगों को भी उन्होंने रोजगार नहीं दिया। उस समय तो विश्व व्यापार संगठन नहीं बना था। यह तो उस से पहले की बात है। इसलिए जो परिस्थितियां पैदा होती हैं तो उन में से मार्ग कैसे निकाला जाए, इस बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। वह विचार न करते हुए केवल यहां आलोचना ही की जाएगी तो उचित नहीं होगा। मैं माननीय सदस्य

को इस बात के लिए अवश्य बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना भाषण समाप्त करते हुए अंन्त में कहा कि हमको राजनीति से ऊपर उठकर इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर इन समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरा विश्वास है कि वह अपनी इस बात पर कायम रहेंगे और सरकार इस बारे में जो कदम उठाएगी उसमें उनका पूरा सहयोग मिलेगा। वह केवल राजनीतिक दृष्टि तक या आलोचना तक अपनी बात को सीमित नहीं रखेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करुंगा। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि आपने दो वर्षों तक क्या किया? इस सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ऐसे कदम उठाए हैं, जो पिछले बीस साल तक नहीं उठाए गए थे। किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए, किसान की फसल का बीमा किया गया। इसके पहले जब किसान की फसल बरबाद होती थी तो राज्य सरकार की ओर से ढाई-ढाई हजार रुपए दे दिए जाते थे, लेकिन यह पहला अवसर है कि केन्द्र सरकार ने अब राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू की है, जिसमें बीमा कराए जाने के बाद अगर किसान की फसल का नुकसान होता है तो एक-एक दाने की क्षतिपूर्ति की जाएगी, उसको कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी। यह व्यवस्था पहले नहीं थी, इस सरकार ने आरंभ की है। इसी प्रकार सिंचाई की बात आती है, इसकी किसान को जरूरत है और इसको बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार की मांग सदन में होती रहती है। मैं माननीय सदन में उदाहरण के रूप में एक योजना का नाम लेना चाहूंगा और वह है सरदार सरोवर योजना। यह योजना महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों के लिए लाभकारी योजना है। सरदार सरोवर योजना ट्रिबुनल में गई थी, ट्रिबुनल ने उसमें वर्ष 1978 में ही निर्णय दे दिया था। वर्ष 1978 के बाद से अब तक वह योजना पूरी नहीं हो पाई है। इसके लिए क्या यह सरकार जिम्मेवार है? जो कुछ इसमें कर सकते थे, वह अगर समय पर करते तो आज यह दिन हमको न देखना पड़ता। आज इसमें काफी विलंब हो गया है। अब अगर माननीय सदस्य कहेंगे कि आप जल्दी से सरदार सरोवर योजना को पूरा करें तो इसके लिए अरबों रुपया एकसाथ कहां से आएगा? यह जो परिस्थितियां, धरातल की परिस्थितियां हैं उन पर अगर हम विचार नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी?

उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है। जी हां, की है और अगर घोषणा की है तो उसके साथ उतनी राशि भी दी है और वह योजना भी प्रारंभ हो गई है। जहां तक विनिवेश का कहा गया, विनिवेश की नीति तो सात-आठ साल पहले तय हुई थी और उसी नीति का यह सरकार पालन कर रही है। उसमें अपनी इच्छा से सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो भी उद्योग अभी तक विनिवेश में लाए गए हैं, उसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है। श्रीमान जी, आपको भी विनिवेश मंत्री जी ने पुस्तिका भेजी है, उसमें आपने देखा होगा कि कितनी पारदर्शिता बरती गई है। सरकार ने या मंत्रिमंडल ने बैठकर यह निर्णय नहीं लिया, उसके लिए कमेटियां बैठाई गईं, जो विशेषज्ञों की समितियां थीं उन समितियों ने निर्णय दिया है। उन समितियों के निर्णय के बाद ही इसे क्रियान्वित किया गया है। इसलिए विनिवेश के मामले में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए प्रमाण दीजिए कि कहां लापरवाही बरती गई है और उसमें सुधार कैसे होना चाहिए उसके लिए सुझाव भी दीजिए तो सरकार उन सुझावों पर विचार कर मानेगी, उसके लिए सरकार तैयार है।

श्री सुरेश पचौरी : आप क्या सरकार की तरफ से बोल रहे हैं?

श्री कैलाश जोशी : मैं सरकार की पार्टी का हूँ। आपकी तरफ से थोड़े ही बोल रहा हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय न लेते हुए कुछ सुझाव अपनी सरकार को देना चाहता हूँ। एक तो सरकार को यह करना होगा कि जो कच्चा माल हमारे देश में उपलब्ध है, उस कच्चे माल को विदेशों में भेजने के बजाय अपने यहां ही उससे बनने वाले सामान के उद्योग स्थापित करने चाहिए, जिनकी हमें आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूंगा। हमारे बस्तर में जो आयरन ओर होता है वह विश्व में सबसे सुपीरियर होता है और उसके लिए सरकार ने पहले जापान से 25 साल के लिए समझौता किया, जापान को यह आयरन ओर जाता रहा। अब जब 25 साल पूरे हो गए तो और 25 साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया। इसके लिए मैं अपनी सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा प्रयास किया जाए कि आयरन ओर या और जो भी कच्चा माल है उसको बाहर न भेजा जाए बल्कि उस पर आधारित उद्योग यहीं पर स्थापित किए जाएं। इसी तरह यहां माननीय सदन में एक बार हमारे माननीय सदस्य ललितभाई मेहता जी या अन्य किसी सदस्य ने कहा था कि गुजरात में बहुत उत्तम श्रेणी का बाक्साइट है, जो चीन भेजा जा रहा है। तो ऐसे जितने भी खनिज पदार्थ हैं और अन्य वस्तुएं हैं, उनको कच्चा बाहर न भेजते हुए हम अपने देश में उनके उद्योग स्थापित करने का प्रयत्न करें।

सरकार ने जो नई नीति बनाई है, उसका कड़ाई से पालन किया जाए। माननीय सदस्य ने अभी यह भी कहा कि वे बैंकों में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, यह नहीं होता, वह नहीं होता। इसको हम भी अनुभव करते हैं कि वास्तव में सरकार जो नीति तय कर लेती है, सरकार जो व्यवस्था बना देती है, निचले स्तर पर उसका पालन नहीं होता है। इसलिए उसका पालन कड़ाई से होना चाहिए।

तीसरी एक अन्य बात मैं यह सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा मिले, लेकिन यह बढ़ावा केवल ग्रामीण लोगों को बैंक से ऋण दिलाने से या उनको गांवों में उद्योग स्थापित करने के लिए कहने से नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें यह करना होगा कि इस प्रकार के लघु उद्योग, ग्रामीण कुटीर उद्योग तो हैं ही लेकिन लघु उद्योग भी, जिनका वास्ता गांवों से पड़ता है या गांवों में जिनके लिए कच्चा माल मिलता है, उनको शहर में लगाने से हमें लोगों को निरुत्साहित करना होगा और इसके लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि सरकार केवल इतना तय कर ले कि जो लघु उद्योग गांवों में स्थापित हो सकते हैं उनको अगर कोई शहर में लगाएगा तो उसको वे सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो गांव में लगाने पर मिलतीं। यह व्यवस्था बड़े उद्योगों में तो अभी है लेकिन लघु उद्योगों के मामले में ऐसा नहीं है। कपड़ा मिलों में बनता है लेकिन गांवों में जाकर रेडिमेड कपड़े बन सकते हैं। ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनके लघु उद्योग क्षेत्र में गांवों में उद्योग लगाए जा सकते हैं ताकि उससे गांवों की बेरोज़गारी समाप्त हो क्योंकि बेरोज़गारी का ज्यादा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र से आता है। पहले यह होता था कि शहर में कारखाने खुलते थे तो गांव के लड़के आ जाते थे लेकिन अब शहरों में ही इतने लड़के बेरोज़गार हो गए हैं कि बाहर वाले के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, वहीं वालों के लिए ही जगह नहीं मिल पाती। इसलिए इस दिशा में भी सरकार को प्रयत्न करना चाहिए।

जो भी लघु उद्योग हैं या ग्रामीण उद्योग हैं, उनमें एक बात की आवश्यकता और होती

है कि उनको ऋण-सुविधा के साथ-साथ कच्चे माल की भी आवश्यकता पड़ती है। उनको कच्चा माल समय पर मिले, ऋण की उचित व्यवस्था समय पर हो और यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो उनको प्रशिक्षण समय पर मिले। यद्यपि सरकार की ओर से प्रशिक्षण की व्यवस्था है किन्तु वह जितनी सुदृढ़ होनी चाहिए, उतनी नहीं है। इसलिए इसकी ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए क्योंकि प्रशिक्षण मिलेगा तो उसके आधार पर वे इन सब कामों को कर सकेंगे। मेरा विश्वास है कि सरकार इस दिशा में अवश्य कदम उठाएगी।

उपसभाध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Sir, I do not know how the Labour Minister has come to take up the Short Duration Discussion. When the labour is not at all being recruited, what will the Labour Minister do? No employment is taking place. The percentage of unemployment is growing. The percentage of employment is also dwindling. It has already reached, so far as the percentage of unemployment is concerned, the figure of 1987-98. The situation is worse than what was existing in 1993, specially in regard to rural employment. There is a very bad situation, a very serious situation. In such a situation, the issue is not concerned with labour, but it is the policy question which is called for. Therefore, even in the Policy Committee of the Cabinet, which decides the economic policy, there should have been someone who can answer the policy-question; he should have taken up the issue. Mr. Vice-Chairman, Sir, they had assured that there would be an employment of 10 million people every year. This was the assurance given during the elections. I do not blame the Government that they could not fulfil the assurance, but, at least, some introspection should have been there, as to why they had failed, as to why they could not implement their assurance. These are the basic questions. ...*(Interruptions)*... Therefore, the thing is that a serious policy-question is involved; whether the pattern of economic policy which we are pursuing to create a labour force will create the labour force or not. This is the basic question.

Sixty per cent or seventy per cent of the labour force in our country is in the agricultural sector. The employment in agriculture has gone down, in absolute terms. A question, Question No.347, was raised in this House on 16th August, 2001, and the answer given was that, in 1993-94, the total employment in agriculture was 242 million; and in 1999-2000, the total employment in agriculture was 236 million. So, employment in

agriculture has gone down, in absolute terms. The Fifty-fifth Report of the National Sample Survey and the Census Report of 2001 say that the number of self-employed in agriculture in the rural areas is going down and that casualisation of labour is taking place. The people who were doing their own jobs are now going back to agriculture. Therefore, the question is serious. The question is whether there will only be a growth-oriented economy or there will be economic growth, combined with equity; whether there will be jobless growth or whether there will be growth with jobs. These are the two basic questions that are posed before the nation. They have to be answered. That is the basic thing. The Report of the Reserve Bank of India, 2000-01, says that employment is not generated commensurate with growth itself. Between 1992-93 and 1996-97, the growth rate was constantly rising. Every year there was an increase in the growth rate. But it was not reflected in the employment. The Report says, "the rate of growth of net fixed capital accumulation increased from 3.6 per cent in the 1970s, to 4.2 per cent in the 1980s and further to 5.3 per cent in the 1990s, with a distinct decline in variability in the 1990s. The growth in employment, however, declined over the period, with some increase in variability in the 1990s". This is the basic question. You are reducing the interest rates. The investment is coming. But that investment doesn't create jobs. The question is whether the Government will change the policy of jobless growth. Now, what had happened was this. Though the growth rate was rising between 1993 and 1997--the decline started afterwards--you had not attended to the question of increasing the employment. Therefore, a demand crunch was created. Now, there is demand. The peculiar economic crisis that our country is facing is the slow-down. It is not the result of the international crisis. It is not created by the international fora. It was generated from within, because there was a demand crunch. This is a policy issue. China is also facing the same problem nowadays. Their export is going down; their import is coming down; the FDI is not coming the way it used to come. But they have maintained a steady growth rate of 7.7 per cent during the past six months of the current year, by expanding the demand in the country. Now, you are handicapped. You cannot expand the means of demand because you have adopted a policy of jobless growth, capital investment, without job creation. The situation is so bad that the growth of employment has declined.

Sir, according to the Census report, the employment growth was 2.04 per cent between 1983 and 1993. It was only 0.94 per cent between

1994 and 2000. It has come down. Which is the industry which has been benefited the most? It is the organised industry which has been benefited. But no growth of jobs has taken place in the organised industry. In such a situation, how are you going to address this issue? You have to answer this question. I would like to quote some figures of both rural and urban unemployment among the age group of 15-29. So far as rural unemployment is concerned, in 1993-94, it was 8.6 per cent. In 1999-2000, it was 11 per cent. So far as urban unemployment is concerned, in 1993-94, it was 15 per cent and today it is 15.5 per cent. If we combine them together, in 1993-94, it was 10.1 per cent which has gone up to 12.1 per cent.

Now I would like to draw the attention of the House and the Government to unemployment amongst youths. It is not a question of employment orientation or wages or earning some money. It is creating a serious cultural problem and because of the growing unemployment amongst youth, cultural degeneration is also taking place. That is one of the important issues which has surfaced. I have seen in many areas that shops are being opened on the roads. In some areas, there is one shop in almost every house. But there are no takers. There are no jobs. People are trying very hard to earn some money. *Jhoparis* are coming up everywhere. A law and order problem is also developing. Sir, job is directly interlinked with civilizational and cultural growth. We are reverting to the old situation. There is total anarchy in the country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please conclude.

SHRI JIBON ROY: I am concluding. The Government should do introspection. There should be a discussion at the national level. If China can do it, why can't we do it? I can understand that increasing population is one of the problems. At the same time, I do realise that if the standard of living is high and if there is social security, population comes down automatically. What has happened in our neighbouring country? The growth of population does not come down automatically. Therefore, there is need for a serious discussion at the national level. Would the Government follow this path? So far as food for work is concerned, the off-take has gone down by two-thirds of the 1987-88 level. In godowns, the stockpiling has gone up to 100 per cent between 1987 and today. After the

hon. Finance Minister made his Budget speech, within a week, the information of starvation deaths started coming. Sir, starvation deaths have never taken place in our country. But starvation deaths took place in Orissa and Andhra Pradesh. The Supreme Court has also admonished the Government. When there are huge stocks of foodgrains, why are starvation deaths taking place?

Therefore, No.1 is that the Food for Work programme has to be liberalised. There are so many strings which should be withdrawn. No.2 is, there should be massive Government investment in development. You are collecting money now to meet the revenue gap. But there should be capital investment, and there should be investment in the public sector. Because of the decline in the growth of organised industries in the public sector, there is a decline in the public sector itself. Manpower increase has not taken place in the public sector. So, there should be investment in the public sector and the Government should re-consider its policy of privatisation and disinvestment. Lastly, I would urge upon the Government to call an all-party meeting and discuss the issue. What will happen is that this Government will go if they continue with this policy, but our nation will be in jeopardy. Therefore, it is not a matter of this side or that side. It is a national question which has to be addressed together by all the parties. Thank you.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa): Sir, I will just raise one point. I would urge upon this Minister to kindly tell us one thing. Godowns are full with wheat; the wheat is rotting. Kindly tell us, when you reply, whether you will give some of these wheat to the people who are starving.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, it is not fair that only one version of it is put here. I would like to tell the House that in addition to the normal allocation, 28,63,000 tonnes of wheat have been allotted free to the States wherever there is demand. Out of these 28,63,000 tonnes, the States have lifted 17 lakh tonnes and they are being distributed. If any Member can bring any problem to my notice, tomorrow itself I will issue orders. Wherever there is drought, the 'Food-for-Work' Programme is needed. The Food-for-Work Programme is going on effectively. On the other hand, the States are saying that they are flooded with wheat. So, they say, "they may send back the wheat." Keeping that in mind, we are doing it cautiously. I would also like to tell my friend, Jibon Royji; whichever State is asking for

allocation under the Food-for-Work Programme, the Government is willing to sanction...

SHRI JIBON ROY: But the condition has to be liberalised. Under the present conditions, nobody can avail of it.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: For the information of this august House, I would like to say that there is no condition so far as the 'Food-for-Work" is concerned. This programme is meant for giving employment to the rural people wherever there is demand. You must be having in your mind the Sampoorna Gramina Rozgar Yojana, where there is some contribution by the States and there are other conditions that are put. As far as the 'Food-for-Work' is concerned, the only condition is, which is also dear to your heart, this should not be used for religious purposes. That is the only condition. Otherwise, you can dig a tank; you can clean the water sources; you can go in for canal desilting; you can go in for tree plantation; you can build schools; you can go in for internal roads; a lot other activities have been allowed under this. Keeping this in mind, and since a wrong message was going, I am sorry, I had to intervene.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mr. Minister, Mr. Faleiro hails from Goa. Whenever it is convenient, we are very polite with him.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: He, fortunately, comes from a State where people below the poverty line are very less in number and the living standards of the people are also comparatively high thanks to tourism and other activities.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): Sir, thank you for allowing me to participate in this discussion on the unemployment situation in the country. With your permission, Sir, I would like to speak in Telugu. It is a pleasure for me to have the concerned Minister here who knows Telugu very well. At least he would receive, whatever I speak, directly, whereas all others would receive it indirectly.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : But he will have to receive it through me.

† SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY : Mr. Vice Chairman Sir, I am glad that we in this House are discussing about unemployment, which is increasing, day-by-day in our country. We may have different views and opinions but as far as this problem is concerned we should rise above politics and work unitedly to solve it. Poverty and unemployment are two sides of a coin. Poverty is nothing but a problem created out of unemployment. In a family there may not be a single person who is employed or adequately employed. In a way, lack of employment is poverty.

An increase in population growth by 2 percent results in an increase in unemployment. The Centre and the State Governments have launched a number of programmes to eradicate both poverty and unemployment. How far are these programmes successful? These schemes are implemented only by the bureaucracy. The local bodies and the Panchayats are neither involved nor given any responsibility in this regard. So, ultimately the Centre and State Governments failed to achieve the desired results of their programmes.

Sir, fortunately the Hon'ble Minister Shri.M.Venkaiah Naidu realized the situation and analysed the reasons for the failure of the programmes. So, he is serious to involve the village Panchayat's, blocks, Talukas, Mandals intermediate panchayats and district panchayats in the implementation of the programmes and is trying his level best to get the expected results. I appreciate such efforts, Sir.

Recently, due to drought and floods a large number of villagers had to vacate their villages. During that time a scheme called 'food for work' was introduced under which rice was distributed unconditionally. This is highly appreciable, Sir. But some State Governments are unable to completely and successfully implement this scheme. But I am proud to say that Andhra Pradesh has been successfully implementing the scheme. Sir, I submit that this scheme would be very useful in our country to create employment at a large scale.

The National Sample Survey organization conducts a survey every five years. Unemployment is continuously growing in spite of the efforts

† English translation of the original speech delivered in Telugu.

made by the Centre and the States and funds spent on their schemes. It may be due to some fault lying with bureaucracy, some lapse in the involvement of the representatives of the people of this country. According to the survey conducted by the NSSO, in 1993-94 the number of the unemployed was 6.03 percent whereas in 1999 it was increased to 7.29 percent of total labour force.

Sir, according to the reply to an unstarred question no. 573 raised in this House on 26th July, 2001 the number of the unemployed in our country is 4,11,96,700. Similarly the answer to the unstarred question no 2149 dated 6th August, 2001 says that by 31st December 2000 the number of the unemployed is 4,13,00,000, which means out of every hundred there are four unemployed persons. These unemployed persons are soft target to be sucked into any subversive activity while those who are employed are busy with their jobs leading a peaceful life. So, it is in the interest of maintaining law and order in the society that we should think about these citizens who are unemployed.

In reply to an unstarred question no. 168 dated 19 November, 2001 the Hon'ble Minister has informed the House that 44,32,680 graduates, 6,47,940 post-graduates and 1,73,670 engineering graduates and 5,69,340 diploma holders are unemployed. Sir, it is really painful to know that the number of the unemployed is so high.

According to NSSO the educated means one who has qualified higher secondary level and above. As per this definition the percentage of the educated unemployed in villages is 57. Similarly there are 63 percent-educated unemployed people in urban areas according to NSSO. These educated people are not inclined to take to agriculture or any other job, which needs physical labour. So, they choose different paths. Some become naxalites, some terrorists and some more choose many others dubious ways for living. So, we have to think of the labour force too which is simultaneously increasing along with the population.

Sir, we do not have much scope in agriculture. Agriculture cannot accommodate more people. So far, public sector undertakings, the Central and State Governments are the only source of employment. We have been implementing economic reforms since 1990. We are stepping into the second phase as far as economic reforms are concerned. It is necessary to

think about downsizing and reducing administrative expenses. It should happen. It is a must. We should all support it. Our finance Minister is emphasizing on increasing GDP growth rate, and reducing fiscal deficit. We are in the second phase as far as the reforms are concerned. These reforms should be beneficial to the country as a whole. It is time to have a closer look at reforms with a view to creating employment opportunities and eradicating poverty. The basic question is; what is the use of the reform process which is unable to resolve the problem of poverty and unemployment? Thus, the reform process will have to be alternated in such a way that it improves the capability of the poor so that they are able to get better employment and, consequently, poverty is reduced. It is, therefore, imperative that the reform processes promote growth with equity and social justice. For this, the policies of employment expansion will have to be adopted rather than employment contraction. The Government will have to play a critical role. The new approaches are needed to tackle unemployment effectively.

Day in and day out, we hear about public sector disinvestments. Privatization programme is going on. When we have given first priority to privatization we need to start many more industries in order to reduce the unemployment problem. We are getting abundant agricultural produce from villages.

Farmers are not getting remunerative prices for their products. We are unable to export or consume this produce. So, we have to start Agro-processing industries, which will make use of the agricultural produce. To start these industries on a higher scale, both the Centre and the State machinery need to work hard. If we start these industries, whatever is the expenditure, it will result in higher national capital reduction in unemployment and increase in GDP. We also need to try to get more foreign direct investment. We need to create more employment opportunities. Government was the main employment-generating agency. It has provided jobs to SC/ST and other downtrodden sections of Society. The jobs in the Central Government and the public sector have been reduced. With this the private sector needs to come forward and generate more jobs even for the socially backward sections.

4.00 p.m.

I fully agree with my colleagues Sh. Suresh Pachouri when he says that we have to rise above politics to solve the problem of unemployment. How to solve this problem has to be discussed, decisions should be taken and these decisions should be implemented too. Once a decision is taken each of us should extend his or her co-operation to the government in solving this problem since the responsibility lies with all of us. With these words I conclude. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I must compliment the translator who translated it so fast. You were going very fast; yet, she kept pace with you. Now, Shri Rahman Khan, you have four minutes.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka) : Mr. Vice-Chairman, Sir, growing unemployment is becoming the most serious problem of our country. Unemployment has a direct connection to the nation's allowed freedom for its citizens. Article 43 of the Constitution is a Directive Principle. It directs, "The State shall endeavour to secure, by sutiable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas." This is what the Constitution desires, whereas it is a reality that unemployment is growing day-by-day.

Sir, in my opinion, unemployment should be the biggest concern of not only the Government but also of the entire Parliament. They should address themselves to the menace of unemployment. Slow-down of the economy is one of the reasons for the growing unemployment. The Government's drastic step to cut down the expenditure by 10% has also resulted in more unemployment. The reasons for the growing unemployment can be many; but the major reasons are, slow-down of the economy, growing sickness in the industry, lack of investment in the

infrastructure sector, defective education policy and lack of direction on the part of the Government.

The NDA Government has pronounced policies and programmes for creating more number of jobs. As Shri Suresh Pachouri rightly said, the Prime Minister had announced that he would be creating 10 crore jobs in ten years. That means, on an average, every year, the Government is committed to create one crore jobs. Two years have passed since then. We would like to know from the Government, out of the 2 crore jobs which it should have created, what is the number of jobs the Government has created as of now. The Government should come out with the data as to how many jobs it has created, out of the 2 crore jobs it was to create.

Sir, poverty and unemployment are two sides of the same coin. Poverty alleviation programme is one of the programmes of the Government in fighting the menace of poverty. Failure to properly implement the poverty alleviation programme is one of the reasons for an increase in the unemployment. Every Government should not confine itself to merely pronouncing its policies. It should, in fact, act. Mere saying that for the past fifty years, nothing has been done, and we would be doing, would not help. It would not comfort you. The past should not be the torchbearer for the future. You should look at the various issues and problems which are creating more unemployment.

Sir, on an average four lakh job seekers register themselves in the Employment Exchanges every year. According to a report, in October 2000, out of four lakh job seekers, they could provide employment to only 13,000 job seekers. So the intensity of the problem has to be understood by the Government. The urgent task on the part of the Government should be nothing other than fighting the unemployment problem. But, unfortunately, that is not happening. The agenda of the NDA Government is other than fighting the unemployment problem. Perhaps, that may not be sounding well to the Treasury Benches. But a reality is a reality. We have to accept the fact then only can we realise and fight this problem and achieve our objectives.

Now I come to the sickness in industry. Today in the morning we were discussing sickness in the small-scale industries. The banks are not financing. New jobs are not being created. How are you going to fight this

problem? Where are the job opportunities created? The infrastructure is not there. No large-scale industry is coming up and foreign investments are not coming in. It is a reality. The small-scale industries are being closed down. It is a reality. So, the Government owes an explanation to the nation as to how they are going to fight the problem of unemployment. In my opinion, the major thing is the education. We have to bring reforms in our Education Policy. As Shri Suresh Pachouri has rightly pointed out, our education is not employment oriented. It is meant only to create white-collar jobs. Now, the Government is not an employer. Hardly any job is being created in the Government sector. Hardly any job is being created in the public sector industries because the public sector is failing. The public sector industries are closed down. Sir, the thrust of the Government should be on those areas where new jobs can be created. The country has a great potentiality of educated and uneducated youth. Sir, 60 per cent of the unemployment is among the educated youth. That is another dangerous signal that we have to recognise. When there is unemployment among the educated youth, it leads to crime and various other problems. There is a need for creating alternative job opportunities. But it should not be in the same old way. Sir, knowledge and skill are the engines of economic growth. There is a need for increasing productivity, competitiveness and generating more demand for skill resulting in the intensification of the national economy. Now it is time that we have to change our Education Policy. We have to tap the skill and services. More job opportunities have to be created in the service sector. Sir, job creation can be boosted by self-employment, but there is no stress on self-employment. No doubt, there are self-employment policies and self-employment programmes, but there is no thrust on them. There is no commitment with regard to self-employment. That is the only area where we have to work. Today the banks are not advancing finances to the tiny sector. *(Time-bell)* Sir, I will take two or three minutes more. Sir, one of the best ways to create employment opportunities is to stress on micro credit and thereby provide credit to the poor. We should also provide skill and training to the poor.

That is what has been done in Bangladesh. Sir, the Government of Bangladesh has provided small and micro credit to benefit nearly 2.2 million families. Now, here, though there is a scheme of micro credit, it has not been implemented properly. So, provide easy credit to the poor, instead of giving them doles, grants, etc. You provide them loans through NGOs, through various other institutions, and see that micro credit is

extended to the poor and slum - dwellers so that we can fight unemployment and we can generate self-employment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please conclude.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Sir, I will conclude in a minute. Then, as I said, we will have to stress on small-scale industries. The small-scale industries are the backbone of our country. In the five or six of our Five-Year Plans, we have given stress on small-scale industries, and the small-scale industries generated a lot of employment. Now, there is a total neglect of this sector because we are expecting foreign investment, we are expecting investment in the capital market, but that is not taking shape. We have seen what has happened with regard to investment in the capital market. So, again, we have to go back to the small and tiny sector, if we want to fight this problem of employment. I would urge upon the Government that by just pronouncing policies, by just pronouncing programmes, we are not going to fight this menace. We can fight this menace only through effective implementation of the policies and programmes which helps in creating employment opportunities in the country. Thank you.

श्री ललितभाई मेहता (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष जी, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण सारा सदन चिंतित है, पूरा देश चिंतित है। बेरोजगारी की जो समस्या आज हमारे सामने है उसको अगर देखेंगे तो पिछले 54 सालों में जो आर्थिक नीतियां अपनायी गयीं उसमें 1991 तक समाजवाद के आधार पर एक आर्थिक नीति हमारे यहां अपनायी गयी, 1991 के बाद मुक्त और स्वतंत्र आधार पर एक नयी नीति का हम अनुसरण कर रहे हैं। आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और खानगीकरण के कारण जो परिणाम या दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं उनसे हम अवगत हैं।

पश्चिम की आर्थिक विचारधारा वैयक्तिक विचारधारा है। इस विचारधारा में सामाजिक पहलू ही नहीं है। हमारे जीवन का आदर्श रहा है - "सर्वे जनः सुखिन भवन्तु"। इसका स्थान पश्चिम की किसी विचारधारा में नहीं है। समाजवाद की अर्थव्यवस्था और आर्थिक विचारधारा जो मार्क्स ने दी वह भी योग्य व्यक्ति या योग्य समुदाय को आगे रखकर चलने वाली थी और उसके कारण 70-80 सालों में यह विफल हो गयी, हमारे सामने यह बात आई। सिर्फ मानव को ध्यान में रखते हुए, मानवता का पक्ष लेते हुए हम सभी आर्थिक नीतियों का सृजन और अवलम्बन करें, इस दृष्टि को अगर ध्यान में रखेंगे तो बेरोजगारी की समस्या और इस समस्या का समाधान इसमें हमको मिलेगा।

उपसभाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी ने पहली सितम्बर को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो बैठक थी उसमें एक निरीक्षण किया था। यह मैं उद्धृत करना चाहूंगा -- Our endowments of productive resources, human, natural, technological and financial, are the envy of the many. However, we are yet to harness them in a manner that yields the best results. यह सिर्फ तीन महीने पहले ही प्रधान मंत्री जी ने निरीक्षण किया है। इस देश में जैसे प्रत्येक व्यक्ति को हमने वोट का अधिकार दिया है, वह राजनीतिक प्रजातंत्र का मूलभूत अधिकार है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले, यह आर्थिक अधिकार, यह प्रजातंत्र का मानदंड मान कर हमको चलना चाहिए। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो बेरोज़गारी की समस्या, जो हमारे सामने है, उसका समाधान निकालने के लिए प्रधान मंत्री जी ने जो बात कही है उस पर हमें सोचना पड़ेगा। जो हमारे मानव संसाधन हैं, जो हमारी जनक्षमता है, उसका हम कैसे उपयोग कर पा रहे हैं, देश के कुदरती संसाधनों का, देश के आर्थिक स्रोतों का और देश की तकनीकी कुशलता का उपयोग हम आर्थिक प्रवृत्तियों के लिए कर पा रहे हैं या नहीं, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। इसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो मेरे सामने जो बात आती है कि 1999 में जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, उसने अपने कार्यक्रम में जो बात कही थी वह बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने है, उसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के सब से बड़े खंड, जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, एक विकास बैंक की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त कारीगरों, लघु उद्योगों, ग्रामीण खादी, हैंडलूम, हस्तशिल्प और इसी तरह के अन्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहयोग संस्थाओं के साथ-साथ सेवा तकनीक और मॉर्केटिंग सुविधाएं भी उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। ये सभी तथा कृषि क्षेत्र को रोज़गार प्रदान करने की असीमित क्षमता है, जिसका उपयोग अब तक नहीं हो पाया है।

उपसभाध्यक्ष जी, हम मानव संसाधन पर ही विचार करेंगे तो यह लगता है कि अगर गेहूं की फसल जिसकी हम मानव श्रम के द्वारा उसकी कटाई वगैरह करते हैं, तो इस देश में जो अभ्यास किया गया उसमें यह बात सामने आई है कि 150 करोड़ मानव दिन, 150 करोड़ मैनडेज़ कैन बी जेनरेटेड बाय अंडरटेकिंग दिस प्रोजैक्ट्स, कि गेहूं की फसल हम मशीन से जो कटवाते हैं उसकी बजाय अगर मानव से कटवाएं तो उसमें लागत थोड़ी ज्यादा आएगी, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि कहां पर मशीन काम करेगी, कहां पर मानव काम करेगा, कहां पर ऑटोमाइज़ेशन और मैकेनाइज़ेशन होगा, कहां पर लेबर इंटेंसिव हमारा काम होगा। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारे देश में जो कुदरती संसाधन हैं, उनका उपयोग हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। एक अभ्यास यह हुआ कि अगर देश में बारिश से आते हुए पानी का हम पूरी तरह से उपयोग करेंगे तो चार लाख करोड़ रूपये की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इस देश में हम उत्पन्न कर सकेंगे, इतनी क्षमता समुद्र में बहते हुए पानी में है। पानी का हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस देश में जितने भी छोटे या बड़े हरीगेशन प्रोजैक्ट्स हैं, उन सब पर अगर हम ध्यान देंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। हमारे देश में जितनी भी प्रोसैसिंग इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना चाहिए और प्रोसैसिंग इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए। अगर यह होगा तो भी रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। देश में जो 32 करोड़ हेक्टेयर जमीन है उसमें से 15 करोड़ हेक्टेयर जमीन का हम खेती के लिए उपयोग करते हैं, और भी चार-पांच करोड़ हेक्टेयर जमीन ऐसी है कि जिसका उपयोग भी हम खेती की दृष्टि से कर सकते हैं। उसको भी अगर हम उपयोग में लायेंगे तो भी रोजगार के अवसर बढ़ने की पूरी

संभावना है। फूड प्रोसैसिंग यह अभी नए जमाने में बहुत आवश्यक जैसी बन गई है, अगर इसका भी उपयोग करना हमने शुरू कर दिया तो भी रोज़गार के कुछ अवसर बढ़ने की संभावना है। फ्लोरीकल्चर और हॉर्टीकल्चर की दिशा में भी हमारे प्रयत्न रहने चाहिए। एक जो बात हमारे सामने विद्वानों ने रखी है कि अगर आप एग्रीकल्चरल सैक्टर में तीन प्रतिशत विकास की दर रख पाते हैं, तो उद्योग के क्षेत्र में 2.6 प्रतिशत विकास अपने आप में होता है। इस के कारण जी.डी.पी. 1.7 प्रतिशत बढ़ती है और अगर जी.डी.पी. 1.7 प्रतिशत बढ़ती है तो आर्थिक विकास की दर 8 प्रतिशत के करीब आ जाती है। तो हमें यह बात ध्यान रखनी होगी। उपसभाध्यक्ष जी, नौवीं पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों को हाई-प्रॉयोरिटी देने की हम ने बात की थी, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यदि लघु उद्योगों के ग्रोथ को हम देखें तो पाते हैं कि वह 6.7 परसेंट रही थी। During the Ninth Five-year Plan, the rate of growth of SSI units has come down to 2.6 per cent. The rate of increase in employment was 4.2 per cent during the Eighth Five-year, which has come down to 2.9 per cent during the Ninth Five-year Plan. During the Eighth Five-year plan, the rate of output, in monetary terms, was 18.2 per cent, and it has also come down to 11.9 per cent in the Ninth Five-year Plan. The increase in the rate of exports was to the tune of 23 per cent. It has also come down to 15 per cent. हमने बात तो यह कही थी कि हम लघु उद्योगों को बढ़ावा देंगे और उन का ध्यान रखेंगे, लेकिन वास्तविक परिस्थिति को हमें ध्यान में रखकर कार्य करना होगा। हमें कुदरती संसाधनों का उपयोग करना होगा। उपसभाध्यक्ष जी, एक बात बताई गई कि देश में 45 हजार मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता पानी में है और 20 हजार मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता पवन में है। तो हम पानी और पवन शक्ति का बिजली के उत्पादन में उपयोग करें, सूर्य शक्ति का बिजली के उत्पादन में उपयोग करें। हमें इन कुदरती संसाधनों का उपयोग आवश्यक रूप से करना होगा।

उपसभाध्यक्ष जी, हमारे गुजरात प्रदेश में कोल बेज मिथेन प्राप्त हुई है, लेकिन केन्द्र सरकार और गुजरात सरकार के बीच में वर्ष 1992 से झगड़ा चल रहा है कि यह किस के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब वह क्षेत्र भी तय कर लिया गया है और गुजरात सरकार ने लाइसेंसिंग पॉलिसी भी मान ली है फिर भी केन्द्र सरकार एक सिग्नेचर करने के लिए दो साल से बैठी है। महोदय, कोल बेज मिथेन में इतनी क्षमता है जिस से कि गुजरात राज्य की 20 साल तक की बिजली की आवश्यकता पूरी हो सकती है। गुजरात की तरह देश के अन्य 5-6 राज्यों में प्राप्त कोल बेज मिथेन के जो डिपॉजिट्स प्राप्त हुए हैं, हमें उन का भी उपयोग इस क्षेत्र में करना होगा।

महोदय, हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा तभी मैं समझता हूं कि हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है, उसे देखते हुए हम नए रोजगार के अवसरों का सृजन कर पाएंगे और उस आधार पर ही देश के विकास को आगे ले जा सकेंगे। आभार। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mr. Virumbi, you have got six minutes.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, the subject which we are now discussing, has already been dealt with in

this august House more than 20 times during the last decade. I apprehend that even after the discussion is over, the purpose for which the discussion was started, is not going to be served. It will not be as we expect it to be. Sir, during the last three decades, the workforce has doubled. The expectation is that during the next decade, the workforce will increase, annually, at the rate of 2.6 per cent. During the 70's, the increase in population was more than what we had expected. Therefore, the problem will be accentuated. We do find some paradox here. In our country, we have a food stock of nearly 600 lakh tonnes with the FCI. But, still, 26 per cent of our population is below the poverty line. Sir, our *per capita* income has increased from Rs.7698/- in 1993-94, to Rs.10,561/- in 2000-2001. Sir, on the one side, there is a surplus of 600 lakh tonnes of foodgrains; on the other, 320 million people are not able to meet even the basic nutritional requirements. Therefore, I would call it a paradoxical situation. Even the hon. Minister, while making an intervention, said that under the Food-for-Work Programme, the Central Government had allocated about 28 lakh tonnes of foodgrains. Out of that, the offtake was only 78.44%. Out of that offtake, only 60.28% of the foodgrains was distributed. Therefore, Sir, out of the total allocation made by the Central Government, only 47.28% actually reached the people.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Vice-Chairman, Sir, as it is going on record, I would like to give the latest figures. The total allocation made is 31,13,085 tonnes; out of which the offtake is 23,89,931 tonnes. Out of the 31,13,085 tonnes of foodgrains, only 17,43,552 tonnes have been distributed so far.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): That means, it is 65%.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Thank you for having provided the latest information. Then, Sir, the number of unemployed people, throughout India, who have been registered with the employment exchanges, is more than 4 crores. Sir, it has been found that, every year, about 8-10 lakhs new people get their names registered with the employment exchanges. Though 62% of our people are engaged in agriculture, their contribution towards GDP is less than 30%. This is the situation, Sir. If our agricultural production is increased by 2-2.5%, it would enhance our GDP by 5% only.

Ours is an agriculture-based country. Earlier also, I have mentioned in this august House that, in USA, only 2% people are engaged in agriculture; in Western Europe, 5% people are engaged in agriculture; in Eastern Europe, 22% people are engaged in agriculture, and, in our country, more than 62% people are engaged in agriculture. Therefore, keeping this in view, we have to see that the economy of the agricultural sector and its allied industries are strengthened. If it is done, I think, it will provide more employment opportunities to the people. Then, Sir, a charge has been levelled that the unemployment situation worsened only after the liberalisation process has started. It is not so. I will give you an example. The share of the Central Government in the overall employment, in 1981 was 20.6%. In 1991, it came down to 17.9% of the total employment. Therefore, the process of slowing down of employment opportunities in the organised sector, particularly, in the Government sector, started in 1981 itself, and not after the liberalisation process. It started in 1981 itself. As regards the public sector and the organised sector, we have to take some action to rectify the mistakes that are natural. Sir, the four years' average of the GDP, in the Ninth Plan, is 5.7 per cent. But, in agriculture and allied industries, the GDP has increased only by 1.3 per cent. Therefore, even though the economy has developed, I am sorry to say, it has developed in a lop-sided manner. So, we have to take a note of it and see that agriculture is also taken, along with the GDP average, which is 5.7 per cent for four years. Otherwise, it will generate a jobless growth. It may affect the growth. ... *(Time bell)*... Sir, please be considerate. Sir, what I want to say is that the unemployment problem is not going to stop with unemployment alone. It is going to affect in another way, *i.e.*, it may give rise to social unrest. Sir, when it reaches the stage of social unrest, I feel, people between the age group of 18 and 30, which is the end of teenage, may lose their belief in the system in which they are living, *i.e.*, democracy. Therefore, it is a very serious question that we have to address ourselves to. If these young people get angry, it is one thing; but if a feeling of disillusionment develops among them, then that would be a different thing altogether. If they get angry, we can satisfy them; but if they get disillusioned, they may think that the system itself has to be changed, which would be a very dangerous thing. Because, Sir, I think, democracy is the only system in which the least mistakes are committed. I feel, if the social unrest grows, it may lead to violence in several parts of the country. So, it would create another problem. Therefore, the unemployment problem should not be seen as an unemployment problem alone. The off-shoot or the fall-out of the unemployment problem will be

more serious; it may even affect the unity and integrity of the country. Therefore, I feel that this is a very serious matter. Now, the question before us is : How do we solve this problem? Sir, in this connection, I want to give some suggestions. I think, firstly, the irrigation potential should be developed. Secondly, the wasteland areas, non-cultivable areas, should be converted into cultivable areas. And, thirdly, power should be generated in such a way that the production is increased; not only production but productivity also. Sir, what do I mean when I say productivity should also be increased? In States like Himachal Pradesh, Uttaranchal and the North-East, we have a lot of potential for power generation. If we concentrate a little more on hydro power generation, I feel, it will subsequently contribute to industrial development. At present, the industrial production is in the doldrums. We have to see that it is improved further. Sir, according to the Planning Commission, in the Tenth Plan, the number of people living below the poverty line will be reduced by 5 per cent, i.e., it will come down from 26 per cent to 21 per cent. We hope that this target will be achieved. But even if we achieve this target, still we will be the fifth largest borrower from the World Bank. Our situation is not so good. So, Sir, when all these types of problems are surrounding us, I feel that we have to take such steps by which agriculture and the allied industries are developed. Otherwise, migration from the rural areas to the urban areas will take place. And, when the people living in the rural areas migrate to the urban areas, automatically, more unemployment will be created. At present, in the urban areas, 58 per cent educated male unemployed and 74 per cent educated female unemployed are there. I feel, when the people migrate to the urban areas, they may not get optimum salary which they ought to have, otherwise, got. Therefore, their salary will be less, if they migrate to the urban areas. And, Sir, when they are not able to cope with the basic needs, jhuggies will come up, and more slums will be created. Obviously, Sir, for the children who are going to born in these jhuggies and slums, the atmosphere will be different; and, in such an atmosphere, after 18-20 years, they will become nothing else but anti-social elements in our society. So, Sir, to stop these people from becoming anti-social elements, we have to see that in the next two decades, no more slums are created in the urban areas. To stop that, the migration from rural to urban areas should be stopped and agricultural and allied services in the rural areas should be developed at a much greater pace than before. With these words, I conclude.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY : That should be replaced by the Balmiki Ambedkar Yojna.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Shri Mohd. Azam Khan. The hon. Member is absent. Shri Rama Sanker Kushik. The hon. Member is absent.

Shrimati Bimba Raikar. Madam, you have got four minutes to speak.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR (Karnataka): Sir, the unemployment problem is a very big problem in our country. There was a time when we used to say that we do not have enough number of educated people, but now in every house we find graduate boys and girls. But, in spite of that they are not getting jobs. Now-a-days the parents take so much of care of their children right from Nursery to XII class or degree, but in spite of that they have to face problems in getting a seat in different courses. Even for getting a seat in the medical or the engineering course, the parents have to pay lakhs of rupees. Till recently the parents wanted their children to become a doctor or an engineer. Yet we find that doctors are without jobs. On the other hand there are so many vacancies in the rural areas and the MBBS doctors are not ready to go there. That is because they want to work only in cities. Earlier there was a rush for engineering courses, but we find that these days mechanical and civil engineers are without jobs and there is a stiff competition. Now, every child wants to become a computer engineer. Every one wants to go to America and get employed there. But, after the September 11 incident, the employment level there too has come down and even the computer engineers employed there are coming back. This is the problem of our children now-a-days. After undergoing so much of trouble and the children becoming degree holders, if they do not get a job, this leads to depression and they resort to drug addiction or are driven to terrorism. If there is no employment for the children, we will be giving a scope for the rise in terrorism or drug addiction. Even though some children want to do some business, I do not think after spending so much money on their education the parents are left with so much money to render them help. Our Government also cannot provide so much of help to set up industries. This is the scenario we are faced with these days.

Sir, the main problem for all this is the growth of our population. So, we have to take care of the growing population, especially in the rural

areas. Just three or four years ago there were big advertisements on family planning on radio and TV and media saying *Kam Bachche, Chhota Sansar* and things like that, but now such advertisements have become less frequent. It is very important to take care of the family planning programme, especially in the rural areas. The Government should give more importance to agriculture because 70 per cent of the population migrate from the rural areas to the cities. In the rural areas, the head of a family spends his entire savings to educate his child and to make him an engineer or a doctor. After getting a degree, the child goes to a city in search of employment. If he does not get a job, the parents become disappointed. So, we should provide more facilities to the agriculturists so that their children do not migrate from the rural areas to the cities. The Government should take care of that.

At the same time, there is a big problem regarding young girls. Mr. Vice-Chairman, Sir, you come from the State of Maharashtra; you know the plight of girls. When a boy and his parents goes to a girl's house to seek a marriage alliance, the first question they put to the girl's parents is, "Is the girl employed?" Nowadays, it is very difficult to run a house if both wife and husband do not earn. That is why the boy's parents put this question just to the girl's parents whether she is employed. The boy's parents also tell the girl's parents, "We do not want any dowry. But you get a job for our son." It' s difficult for the girl's parents to find a job for the boy. Nowadays, so many young girls are remaining without marriage because of the unemployment problem. It has become a difficult problem for the parents also. Keeping all these things in mind, the Government of India should take special care and try to solve the unemployment problem that is increasing in the country. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mrs. Saroj Dubey. Madam, you have five minutes. Today, I have given you the maximum time, 20 minutes in all.

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : ठीक है, मैं आज आपकी बात रखने का प्रयत्न करूंगी। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगी। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। बहुत ही गंभीर और ज्वलंत समस्या के संबंध में इस सदन में चर्चा हो रही है और जैसे-जैसे इस पर विचार होता चला जा रहा है यह समस्या और भी बढ़ती चली जा रही है। मुझे याद है पिछले सत्र में इस पर बड़े जोरशोर से बहस हुई थी, लेकिन उसका नतीजा ज्यों का त्यों रहा है, बेरोजगारी बढ़ ही रही है, घटने का सवाल ही नहीं है। नववर्ष के उपलक्ष्य में

माननीय प्रधान मंत्री जी ने खुशहाली की कामना के बजाय बेरोजगार युवकों, सरकारी कर्मचारियों और नियोजित मजदूरों को काम से हटाये जाने तथा स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने और नौकरियों के लिए सरकार के पास न आने और खान के मालिकों का दरवाजा खट-खटाने का सुझाव दिया। यह गणतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी की बहुत इज्जत करते हुए कहना चाहती हूं कि यह बहुत खतरनाक और निराशाजनक है। यदि बेरोजगारी की समस्या ज्यादा बढ़ गई तो उसे सरकार सम्भाल भी नहीं पायेगी और देश में अराजकता फैल जायेगी। आज हम देख रहे हैं कि इस देश में नक्सलाइट है, अराजकता फैली हुई है, कानून व्यवस्था भंग होती चली जा रही है। इसके पीछे एक कारण बेरोजगारी का भी है। इसीलिए इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। प्रधान मंत्री जी ने स्वनियोजन की भी बात की है लेकिन उसके लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की कैसे व्यवस्था की जाए उसका कभी कोई प्रयास दिखाई नहीं दिया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था मैकाले की नीति पर आधारित है जो केवल क्लर्क तैयार कर सकती है या एम.ए., पी.एच.डी. की डिग्री दे सकती है। जब कोई नौजवान इस डिग्री को लेकर निकलता है तो वह नौकरी के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है क्योंकि वह श्रम नहीं करना चाहता है, श्रम करने में उसकी बेइज्जती होती है। ऐसी स्थिति में सरकार पहले यह तो बताये कि उसे कितने शिक्षित लोगों की नौकरी के लिए जरूरत है, कितने कुशल लोगों की नौकरी के लिए जरूरत है, कितने कारीगरों की नौकरी के लिए जरूरत है। वह पहले यह तो स्पष्ट करे। जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, वैसे-वैसे शिक्षित बेरोजगारों की समस्या भी विकट होती चली जा रही है। अब सरकारी नौकरी पाना तो एक ख्वाब होता चला जा रहा है, एक सपने की तरह से होता चला जा रहा है। जिस हिसाब से देश की आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। देश की आबादी 2.1 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और बेरोजगारी 2.56 की दर से बढ़ रही है। सरकार ने एक तरफ तो 2002 तक पूर्ण रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष एक करोड़ स्थायी रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। उसके लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। महोदय, रोजगार सृजन की बात तो दूर रही, जो लोग रोजगार में हैं, उन्हें भी लाखों की संख्या में निकाला जा रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। एक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1998 में रोजगार वृद्धि दर सरकारी क्षेत्र में .09 प्रतिशत रही, निजी क्षेत्र में 1.72 प्रतिशत रही, संगठित क्षेत्र में 0.46 प्रतिशत रही। यह दर 1999 में और कम हो गयी। सरकारी क्षेत्र में वृद्धि बिल्कुल शून्य हो गयी। निजी क्षेत्र में 0.099 प्रतिशत हो गयी, संगठित क्षेत्र में .04 प्रतिशत रही। उम्मीद यह थी कि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की वृद्धि हो जाएगी और निजी क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर निर्मित होंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होने ही थे क्योंकि संगठित क्षेत्र में तो पहले ही 8 या 9 प्रतिशत लोग काम करते हैं। ...(व्यवधान)... महोदय, मैं जल्दी समाप्त कर दूंगी। रोजगार की संभावना वाला जो हमारा कृषि क्षेत्र है, उसकी जो उपेक्षा की जा रही है, वह इस बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। एक इकनॉमिस्ट का मानना है कि भारत के एक चौथाई से कुछ अधिक किसान मिलकर देश के 60 फीसदी उत्पादों का उत्पादन करते हैं। अर्थशास्त्रियों का भी यह मानना है कि 1991 में उदारीकरण की शुरुआत के बाद से कृषि विकास की दर घटी है और कृषि आज फायदे का सौदा नहीं रह गया है क्योंकि कृषि से संबंधित आयात को फ्री कर दिया गया है और निर्धारित मूल्य उत्पादन लागत से कम हो गए हैं इसलिए लोगों का ध्यान कृषि से हट रहा है जब कि कृषि में बहुत ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं। उससे जो तैयार होने वाले उत्पाद हैं,

उनकी भी बहुत संभावनाएं हैं इसलिए कृषि की ओर हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने चाहिए। किसानों को सब तरह की मदद दी जानी चाहिए। इसके साथ ही अधिक रोजगार की संभावना वाले बानगीकरण पर पर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त बंजर भूमि का विकास किया जाना चाहिए। महोदय, लघु उद्योग जो हमारे देश को सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या के मुताबिक पिछले 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि में औसतन करीब दो प्रतिशत की वृद्धि होगी। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक 1997 से 2002 के बीच में श्रम शक्ति में 2.5 फीसदी की दर से सालाना वृद्धि दर होगी परन्तु रोजगार में वृद्धि की दर इससे कम है। इसके अतिरिक्त जो वी.आर.एस. देकर श्रमिकों की छंटनी की जा रही है, उसके कारण आम आदमी शेयर बाजार का जुआरी बनकर रह गया है और मुम्बई तथा कोलकाता में लोग सपरिवार आत्महत्याएं कर रहे हैं जो शेयर बाजार में बर्बाद हो गये, उनकी दास्तान से इसकी गहराई को समझा जा सकता है। महोदय, आज उदारीकरण के चलते रोजगार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महिलाओं की उपेक्षा हो रही है। नयी तकनीक के प्रवेश ने महिलाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया है क्योंकि महिलाएं ज्यादातार अकुशल होती हैं। वे किसी तरह से काम करके अपने परिवार का पेट पालती हैं। महोदय, आपको मालूम होगा कि 40 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं अपने परिवार की मुखिया होती हैं। वे या तो विधवा हैं, या अपने परिवार की मालिक हैं या उनके पति उन्हें छोड़ गये हैं, उन लोगों को बहुत कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के लिए समान काम, समान वेतन का कोई नियम लागू नहीं हो रहा है जब कि यह कानून है। इसलिए निजी और सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित होनी चाहिए। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि महिलाएं ही प्रथम शिक्षिका होती हैं, मां ही प्रथम शिक्षिका होती है इसलिए सभी प्राथमिक स्कूलों में महिलाओं को ही अध्यापिका रहना चाहिए। इससे उनको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। महोदय, कृषि क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 15 प्रतिशत कम काम मिलता है और गैर कृषि क्षेत्र में 18 प्रतिशत कम काम मिलता है। महिलाओं को ग्रामीण इलाकों में केवल 137 दिवस काम करने को मिलता है जबकि पुरुषों को 172 दिन मिल जाता है। यह आंकड़ा देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि महिलाओं की क्या स्थिति है। 1996 में 167.94 पुरुषों को नौकरी दी गई और महिलाओं को केवल 26 प्रतिशत नौकरी दी गई। 1998 में पुरुषों को नौकरी दी गई, 166.55 और महिलाओं को 27.63 प्रतिशत। दोनों में कितना अंतर है। महिलाओं की बड़ी ही दयनीय स्थिति है ...**(व्यवधान)**... सर, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि नौजवान तो कुछ भी कर सकता है ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : मंत्री जी, महिलाओं की स्थिति के बारे में सुनिए। महिलाओं पर बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियां महिलाओं पर किस तरह कहर बरपा रही हैं। उनके बारे में जो बातचीत हो रही है, कृपया उसको सुनिए। मैं चाहूंगी कि जब आप जवाब दें तो इस बारे में जो आपका आकलन है, उससे सदन को अवश्य अवगत कराएं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I am confident that you have intervened to give some breathing space. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सरोज दुबे : महिलाएं इस देश की आधी आबादी हैं और जैसा मैंने अभी बताया कि 40 प्रतिशत महिलाएं हैड आफ दि फैमिली हैं। इस देश के भावी नागरिक को पालने और अच्छा नागरिक बनाने का काम महिलाएं करती हैं। यदि उनके हाथ में रोजगार नहीं होगा तो मुझे माननीय मंत्री जी से दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में महिलाओं को अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए अपने तन का सौदा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये पूंजीपति महिलाओं के शरीर का प्रदर्शन करके अपना उत्पाद तो अच्छे दामों पर बेचते हैं लेकिन महिलाओं के खाली हाथ को नौकरी देने का काम नहीं करते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जब हम बेरोजगारी की समस्या पर विचार कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : यह मार्किट इकोनोमी की है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरोज दुबे : जब हम महिलाओं की बेरोजगारी की समस्या पर विचार कर रहे हैं तो महिलाओं के रोजगार के संबंध में जरूर कुछ करने का अपना विचार बनाएं और महिलाओं के हाथों को रोजगार दें क्योंकि अगर महिलाओं के हाथ में रोजगार नहीं रहेगा तो हमारे देश का भावी नागरिक अच्छा नागरिक नहीं बन पाएगा, मूल्य सिद्धांत वाला नागरिक नहीं बन पाएगा। अगर हमारे नागरिक अच्छे नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माननीय मंत्री जी समाजवादी नेता रहे हैं और हमेशा महिलाओं के प्रेरक रहे हैं ...**(व्यवधान)**... पुरानी बात है तो क्या हुआ, विचारधारा तो उनकी वही है, चाहे वे कहीं चले जाएं। ...**(व्यवधान)**... इसलिए मेरा यह निवेदन है कि महिलाओं के रोजगार पर विशेष ध्यान दें। आप नौजवानों और बाकी लोगों पर ध्यान देते हैं, कृषि क्षेत्र में समान वेतन का काम करते हैं और जब लघु उद्योग व कुटीर उद्योग गांव-गांव में जा सकते हैं तो उनमें महिलाओं को सुलभ ऋण के वितरण की व्यवस्था करें। उनको तकनीकी शिक्षा दें। महिलाओं को केवल कुकिंग और सिलाई की ट्रेनिंग देते हैं। उनको कम्प्यूटर की ट्रेनिंग दीजिए और नई-नई चीजों की शिक्षा दीजिए। उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लायक नई-नई शिक्षा दीजिए ताकि वे भी पुरुषों के साथ शामिल हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह अनुरोध करुंगी और सदन से भी मांग करुंगी कि महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया जाए और उनके हाथ को काम दिया जाए ताकि वे परिवार का पालन-पोषण कर सकें और मजबूत व सशक्त नारी बनकर देश को आगे बढ़ाने वाले नागरिकों को इस देश को समर्पित कर सकें।

उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोडकर) : जब-जब आप समस्या का समाधान करती हैं, आपके विचारों की स्पीड देखकर मुझे ताज्जुब होता है। There is a message from the Lok Sabha, Mr. Secretary-General.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Explosive Substances (Amendment) Bill, 2001

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-